

आज झूम उठा शेयर बाजार

निवेशकों को 5 लाख का फायदा हुआ है

मुंबई, 10 अप्रैल. अमेरिका-ईरान के बीच स्थायी युद्ध विराम के लिए जारी वार्ता के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को तेजी लौट आयी और बीएसई का सेंसेक्स 918.60 अंक (1.20 प्रतिशत) चढ़कर 77,550.25 अंक पर पहुंच गया।



स्थायी युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान में आज से हो रही वार्ता से बाजार में निवेश धारणा को मजबूती मिली है। चौरफा लिवाली के बीच मझौली और छोटी कंपनियों में निवेशकों ने ज्यादा पैसा लगाया। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.27 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.65 प्रतिशत ऊपर बढ़े। आईटी की 1.91 फीसदी की गिरावट को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक हरे निशान में रहे। ऑटो में सबसे अधिक 2.85 प्रतिशत की तेजी रही। बैंकिंग, वित्त और रियलटी सेक्टरों के सूचकांक भी दो प्रतिशत चढ़े।

सेसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स का शेयर चार प्रतिशत के करीब मजबूत हुआ। आईसीआईआई बैंक में भी तीन फीसदी से अधिक की बढ़त दर्ज की गयी। निवेशकों को 5 लाख का फायदा हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिगो, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर दो से तीन प्रतिशत बढ़े। अडानी पोर्ट्स, ट्रेड, एचडीएफसी बैंक, एलएडबी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पावरग्रिड, टाटन, अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंदुस्तान यूनीलिवर के शेयर एक से दो प्रतिशत तक ऊपर बढ़े हुए। इटनल, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील, बीएसएल, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल और आईटीसी के शेयर भी हरे निशान में रहे। सनफार्मा का शेयर साढ़े तीन फीसदी से अधिक टूट गया।

कारोबार में रुपया हुआ तीन पैसे मजबूत

मुंबई, 10 अप्रैल. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद रुपया अंत में तीन पैसे चढ़कर 92.51 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा 52 पैसे की मजबूती के साथ 92.54 रुपये प्रति डॉलर पर रही थी। रुपये पर आज शुरुआती कारोबार में दबाव देखा गया। यह 10 पैसे की गिरावट में 92.64 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। दोपहर के बाद एक समय यह 92.92 रुपये प्रति डॉलर तक टूट गया था। लेकिन बाद में वापसी करते हुए 92.51 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने आज पूंजी बाजार से 18 करोड़ डॉलर निकाले। पिछले कारोबारी दिवस की बड़ी गिरावट के बाद गुरुवार को कच्चे तेल में तेजी रही।

आईटीआर 1 फार्म में दिखा सकते हैं दो मकान

इस साल आईटीआर पुराने कानून से भरे जाएंगे
जल्द ही फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद



आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तक की गई है, इसलिए समय रहते तैयारी करना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो चुका है, लेकिन इस साल भरे जाने वाले रिटर्न पुराने नियमों के तहत ही होंगे, जिससे टैक्सपेयर्स को ज्यादा बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर विभाग ने आईटीआर-1 फॉर्म में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब आप दो मकानों से होने वाली आय दिखा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जो पहले सिर्फ एक घर की आय दिखाते थे, वे अब क्लियर टैक्स आईटीआर-1 का उपयोग कर सकते हैं।

सैलरीड कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 एक अहम दस्तावेज होता है, जिसके बिना सही तरीके से रिटर्न भरना मुश्किल होता है। यह फॉर्म आमतौर पर नियोजकों द्वारा जून तक जारी किया जाता है, इसलिए कई लोग इसके बाद ही आईटीआर फाइल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उसे लेट फीस और अन्य दंड का सामना करना पड़ सकता है। इस साल एक बड़ा बदलाव यह है कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो चुका है, जिसने पुराने 1961 के कानून की जगह ली है।

डीएम में देरी से कर्मचारी हैं नाराज 60 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद

नई दिल्ली, 10 अप्रैल. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता का इंतजार इस बार लंबा होता जा रहा है। जनवरी 2026 से लागू होने वाले डीएम के ऐलान में देरी ने कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है।

इस बीच कर्मचारी संगठनों ने निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जल्द घोषणा करने की मांग की है। हर साल सरकार मार्च के आसपास डीएम बढ़ोतरी का ऐलान करती रही है, लेकिन इस बार अप्रैल तक भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इससे कर्मचारियों के बीच तरह-तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगी हैं—कुछ लोग तो यह तक सवाल उठा रहे हैं कि कहीं कोरोना काल की तरह डीएम पर रोक तो नहीं लगाई जाएगी। हालांकि, मौजूदा गणनाओं के आधार पर 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे डीएम 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो सकता है। लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक असमंजस बना हुआ है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता का इंतजार इस बार असामान्य रूप से लंबा हो गया है। जनवरी 2026 से लागू होने वाले डीएम के ऐलान में देरी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच असंतोष और चिंता बढ़ा दी है। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने निर्मला सीतारमण से जल्द घोषणा करने की अपील की है।

भारतीय डॉक्टर ने रचा मेडिकल इतिहास

मुंबई से मस्कट तक रोबोटिक सर्जरी का कमाल
सीमा पार सर्जरी- भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड



मुंबई, 10 अप्रैल. विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 के अवसर पर, जिसका इस वर्ष का संकल्प है-स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ अटूट, कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल ने वैश्विक चिकित्सा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है। विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की एक विस्मयकारी मिसाल पेश करते हुए, डॉ. टी. बी. युवराजा ने मुंबई में बैठकर मस्कट (ओमान) के मेडिकल सिटी अस्पताल में भर्ती एक 55 वर्षीय महिला की सफल रोबोटिक

कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल के एनजीयुटिव डायरेक्टर और सीईओ, डॉ. संतोष शेठ्टी ने इस गौरवशाली उपलब्धि पर कहा—यह विकास अस्पताल के तकनीकी नेतृत्व और रिमोट रोबोटिक सर्जरी में हमारी पिछली सफलताओं की अगली कड़ी है, जो मेडिकल इन्वोलूशन के क्षेत्र में हमारी अग्रणी स्थिति को और भी मजबूत करता है। कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल और डॉ. युवराजा आधुनिक टेलीसर्जरी की सीमाओं को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं—इस बार भारत की सशक्त विलिनिकल क्षमताओं का विस्तार मस्कट के एक कैसर रोगी तक किया गया है। दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणालियाँ आज विशेषज्ञता और सुलभता के बीच की खाई को पटाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में यह उपलब्धि एक बड़े बदलाव का शंखनाद है—एक ऐसा भविष्य जहाँ भौगोलिक दूरियाँ बेमानी होंगी, इलाज हर किसी की पहुँच में होगा और भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा।

रेंडिकल नेफ्रेक्टोमी (किडनी निकालने की जटिल सर्जरी) संपन्न की। अत्याधुनिक मेडबॉट रोबोटिक सर्जरी सिस्टम के जरिए अंजाम दी गई यह ऐतिहासिक प्रक्रिया भारत की पहली क्रॉस-बॉर्डर रिमोट रोबोटिक सर्जरी मानी जा रही है। यह उपलब्धि उस भविष्य की ओर एक निर्णायक कदम है, जहाँ भारतीय डॉक्टरों की विशेषज्ञता भौगोलिक सीमाओं को लांघकर दुनिया भर के मरीजों को वास्तव में जीवनदान दे सकेंगी अत्याधुनिक रोबोटिक प्रणालियों और निर्बाध रियल-टाइम कनेक्टिविटी की मदद से, इस सर्जरी को असाधारण सटीकता और नियंत्रण के साथ पूरा किया गया। इस सफलता ने दुनिया के सामने क्रॉस-बॉर्डर रिमोट सर्जरी की विश्वसनीयता और क्लिनिकल सक्षमता का लोहा मनवाया है।

गोल्ड-सिल्वर में आई एक प्रतिशत तक की गिरावट



नई दिल्ली, 10 अप्रैल. कमांडिटी बाजार में शुक्रवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों का मूड कुछ ठंडा पड़ा। एमएसएक्स पर दोनों कीमतें धातुओं में करीब 1 प्रतिशत तक की कमजोरी देखने को मिली। इसका मुख्य कारण निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली और सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन) की मांग में कमी को माना जा रहा है। हाल के दिनों में वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते सोना-चांदी में तेजी देखी गई थी, लेकिन अब निवेशक ऊंचे स्तरों पर मुनाफा बुक कर रहे हैं। सोना जहाँ 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी भी 2.42 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर के आसपास फिसलती नजर आई। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में अभी भी रुचि बनी हुई है, लेकिन मजबूत तेजी के लिए जरूरी मोमेंटम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। एमएसएक्स पर सोना करीब 0.56 प्रतिशत गिरकर 1,52,561 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्रडे लो तक पहुंच गया। वहीं, चांदी (5 मई वायदा) भी लगभग 0.7 प्रतिशत गिरकर 2,42,067 रुपये प्रति किलोग्राम पर आई।

व्हाट्सअप की प्राइवैसी सवालों के घेरे में

यूजर्स के मैसेज पढ़ने के आरोप को मेटा ने साफ-साफ नकारा
मस्क ने एक्स चैट को बताया ज्यादा सुरक्षित विकल्प



वॉशिंगटन, 10 अप्रैल. दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सअप की प्राइवैसी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। टेलीग्राम के सीईओ और पावेल दुराव जैसे बड़े टेक लीडर्स ने इस प्लेटफॉर्म की सुरक्षा पर खुलकर हमला बोला है। मस्क ने जहाँ इसे भरोसे

लायक नहीं बताया, वहीं डुरोव ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा एन्क्रिप्शन फ्रॉड तक कह दिया। यह पूरा विवाद अमेरिका में दायर एक क्लास एक्शन मुकदमे के बाद शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सअप अपने यूजर्स के निजी मैसेज को इंटरसेप्ट कर रहा है और थर्ड पार्टी कंपनियों के साथ साझा कर रहा है। व्हाट्सअप की प्राइवैसी को लेकर छिड़ा विवाद अब वैश्विक बहस का रूप ले चुका है। हाल ही में कैलिफोर्निया के फेडरल कोर्ट में दायर एक क्लास एक्शन मुकदमे में दावा किया गया है कि कंपनी अपने यूजर्स के मैसेज को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के बावजूद इंटरसेप्ट करती है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये डेटा अक्सर 'जैसी थर्ड पार्टी कंपनियों के साथ साझा किया जा सकता है'। हालांकि, मेटा प्लेटफॉर्म ने इन आरोपों को बेतुका और झूठा बताया है।

इंडिगो ब्लूचिप से एप्पल खरीद पर मिलेगा रिवाँड

नई दिल्ली, 10 अप्रैल. देश की प्रमुख विमान सेवा कंपनी इंडिगो के ब्लूचिप सदस्य अब आईप्लेनेट पर एप्पल के उत्पाद खरीदकर रिवाँड चार्ज पा सकते हैं। इंडिगो ने इसके लिए एप्पल के प्रीमियम पार्टनर आईप्लेनेट के साथ करार किया है। एयरलाइंस द्वारा शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञापन में बताया गया है कि ब्लूचिप सदस्य आईप्लेनेट के समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से और देश भर में इसके 78 से अधिक खुदरा

स्टोर पर की गयी खरीदारी पर इंडिगो ब्लूचिप कमा सकते हैं। यह ऑफर आईफोन, मैकबुक, आईपैड, एप्पल की घड़ियाँ, एयरपॉड और प्रीमियम एक्ससेसरीज की विस्तृत रेंज पर लागू है। इस करार से इंडिगो ब्लूचिप पोर्टफोलियो के तहत रिवाँड के अवसर और कमाई का दायरा बढ़ा है। इंडिगो के मुख्य डिजिटल एवं सूचना अधिकारी नीतान चोपड़ा ने कहा कि आईप्लेनेट के साथ हमारी साझेदारी एक विचारशील और रणनीतिक पहल है।

डिजिटल फ्रॉड पर अब लगेगी रोक

नई दिल्ली, 10 अप्रैल. देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल फ्रॉड के बीच आरबीआई एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो 10,000 से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट तुरंत नहीं होंगे, बल्कि उनमें 1 घंटे का होल्ड लगाया जा सकता है।



इस कदम का मकसद यूजर्स को गलत ट्रॉजैक्शन को रोकने या कैसिल करने का मौका देना है। आज के समय में एनपीसीआई के जरिए होने वाले ज्यादातर डिजिटल ट्रॉजैक्शन सेकंड्स में पूरे हो जाते हैं। लेकिन इसी तेजी का

70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 50,000 से ज्यादा के ट्रॉजैक्शन पर एक ट्रस्टेड पर्सन की मंजूरी अनिवार्य हो सकती है। इसके अलावा, यूजर्स को व्हाट्सअप फीचर भी मिलेगा, जिससे वे भरोसेमंद लोगों या मर्चेंट्स को जोड़ सकेंगे और उनके साथ होने वाले ट्रॉजैक्शन में देरी नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण सौभाग्य डिजिटल पेमेंट सेवाओं को तुरंत बंद कर सकेगा। यह फीचर फ्रॉड की स्थिति में तत्काल सुरक्षा प्रदान करेगा।

समाचार विशेष

नैया पार करने को निषादों को साध रहे दल

भाजपा और सपा में मिलने लगी नेताओं को तवज्जो

लखनऊ. यूपी विधानसभा के अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक दल निषादों का वोट बैंक साधने की कवायद में लग गए हैं। भाजपा द्वारा निषाद समाज की पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाने और सपा द्वारा पूर्व सांसद फूलन देवी की बहन रुक्मिणी निषाद को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करने के पीछे यही निहितार्थ निकाले जा रहे हैं।



उधर, चुनाव करीब आते देख निषादों की अगुवाई करने वाले दल भी रैलियों और जनसभाओं के जरिए बड़े दलों को यह संदेश देने में लग गए हैं कि चुनावी नैया की सियासी

भाजपा हो या फिर सपा, सभी का प्रयास है कि निषाद समाज उनके साथ रहे। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि निषाद समाज की सबसे बड़ी मांग उनके समाज की अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की है। जो राजनीतिक पार्टी इस दिशा में कुछ करने की बात कही, समाज का वोट उसी पार्टी को जाता रहा है। निषादों का वोट बैंक ही ताकत-वैसे तो यूपी के हर क्षेत्र में निषादों की ठीक ठाक आबादी है, लेकिन गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मीरजापुर, भदोही, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, बांदा, हमीरपुर, सहारनपुर और लखीमपुर जिलों में निषाद बाहुल्य आबादी मानी जाती है।

निषाद पार्टी की यूपी में पैठ

यूपी में निषादों के वोट बैंक पर डॉ. संजय निषाद की अगुआई वाले निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) की अच्छी पैठ मानी जाती है। इसी के बल पर निषाद पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ मिल कर 16 सीटों पर अपनी पार्टी के नेताओं को प्रत्याशी के रूप में उतारा था। इनमें से दस सीटों पर प्रत्याशी निषाद पार्टी के सिंबल पर उतरे थे, जिसमें छह जीते थे। निषाद पार्टी के छह नेता भाजपा के सिंबल से मैदान में उतरे थे, जिसमें से पांच जीते थे।

91 लाख लोगों की पहचान पर संकट

बंगाल में लोकतंत्र की सबसे बड़ी 'छंटनी'

कोलकाता. एक आम आदमी के लिए उसका 'वोट कार्ड' केवल मतदान का अधिकार नहीं, बल्कि इस देश में उसके होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल के 90,83,345 लोगों के सिर पर अपनी पहचान खोने की तलवार लटक रही है।



चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार, राज्य में मतदाताओं की एक बहुत बड़ी आबादी को सूची से बाहर कर दिया गया है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मुर्शिदाबाद और 24 परगना में सबसे ज्यादा असर-चुनाव आयोग की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा गाज अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले पर गिरी है, जहाँ से 4,55,137 नाम हटा दिए गए हैं। इसके बाद उत्तर 24 परगना का नंबर आता है, जहाँ 3,25,666 लोग अब वोट नहीं रहे हैं। इसके अलावा कुर्चबिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा और दक्षिण 24 परगना जैसे सीमावर्ती जिलों में भी भारी छंटनी हुई है। न्यायिक अधिकारियों ने गहन जांच के बाद पाया कि लाखों लोग मतदाता सूची में रहने की पात्रता खो चुके हैं। अभी और बढ़ सकती है संख्या-यह पूरी प्रक्रिया एसआईआर के तहत की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 60,06,675 मामले न्यायिक जांच के घेरे में थे, जिनमें से 59,84,512 मामलों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

नवजोत कौर ने बनाई भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी



क्या है उनका 'गोल्डन पंजाब' प्लान

चंडीगढ़. कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर क् सियासी तापमान बढ़ा दिया है। नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी रखा गया है। यह घोषणा पंजाब विधानसभा चुनाव से लगभग एक साल पहले

की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य पंजाब को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाना है। बता दें कि नवजोत कौर, पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि लंबे समय तक राजनीतिक नेताओं के प्रदर्शन को देखने और समझने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प को तैयार करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वह अपना जीवन देश के लिए समर्पित करना चाहती हैं और लोगों को उनका हक दिलाना चाहती हैं।

गोल्डन पंजाब बनाने का वादा उन्होंने गोल्डन पंजाब बनाने का वादा करते हुए कहा कि राज्य को फिर से ऐसा बनाया जाएगा जहाँ प्यार, भाईचारा, न्याय और स्वतंत्रता का माहौल हो, और लोग बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकें। गौरतलब है कि पिछले साल नवजोत कौर ने मुख्यमंत्री पद को लेकर 500 करोड़ रुपये की मांग किए जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। 31

विशेष बह रही थी शराब की नदियां, ईसी की चुनावी राज्यों में बड़ी कार्रवाई

वोट के बदले 'बोतल' और 'नोट'!

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में रिवार तक इलेक्शन फ्लाइंग स्क्रायड और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कुल 319 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, शराब और अन्य मुफ्त वस्तुएं जब्त की गई हैं। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। चुनाव वाले पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से बंगाल मुफ्त उपहारों (150 करोड़ रुपए), शराब (55 करोड़ रुपए), कीमती धातु (39 करोड़ रुपए) और नकदी (11 करोड़ रुपए) की बरामदगी के मामले में सबसे आगे है, जिनका कथित तौर पर मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बयान में कहा गया है कि 23 और 29 अप्रैल को होने



राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव अधिकारियों द्वारा जब्त की गई 29.63 लाख लीटर शराब को भी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 21.29 लाख लीटर शराब जब्त की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव से पहले असम में फ्लाइंग स्क्राइड और निगरानी टीमों ने 4 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। राज्य में नकदी के अलावा 20 करोड़ रुपए मूल्य की 6,84,627 लीटर शराब भी जब्त की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि 5 अप्रैल तक असम में 56 करोड़ रुपए की ड्रस, 4 करोड़ रुपए की कीमती

तमिलनाडु में भी हुई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि असम में अब तक बरामद मुफ्त उपहारों और प्रतिबंधित वस्तुओं का कुल मूल्य 97 करोड़ रुपए है। तमिलनाडु में कुल मिलाकर 170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें 67 करोड़ रुपए की ड्रस, 63 करोड़ रुपए की अन्य मुफ्त वस्तुएं, 30 करोड़ रुपए नकद, 8 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं, और 2 करोड़ रुपए की शराब शामिल है। केरल में चुनाव आयोग ने कुल 58 करोड़ रुपए मूल्य की रीशत की वस्तुएं बरामद की हैं।